आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2018–19 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम तथा अन्तिम किश्त प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. यह अनुपूरक मांगें कुल ₹ 3142 करोड़ 65 लाख की हैं, जिनमें से ₹2021 करोड़ 69 लाख गैर–योजना स्कीमों, ₹671 करोड़ 26 लाख योजनागत स्कीमों तथा ₹449 करोड़ 70 लाख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु प्रावधित किए गये हैं।

3. गैर–योजना व्यय में मुख्यतः ₹1438 करोड़ 70 लाख Ways & Means Advance हेतु प्रावधित किए गए हैं। लगभग ₹144 करोड़ शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड के विद्युत प्रभारों को चुकता करने व भू–अधिग्रहण मुआवज़े की अदायगी, ₹98 करोड़ 91 लाख बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ उपदान इत्यादि के लिए, ₹73 करोड़ 97 लाख धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यकरण व पार्किंग स्थल विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण, ₹60 करोड़ 96 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान इत्यादि, ₹31 करोड़ 16 लाख विभिन्न सड़कों के निर्माण और न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में मुआवज़े के भुगतान, ₹29 करोड़ 50 लाख सामाजिक सुरक्षा कल्याण, ₹18 करोड़ 98 लाख विधान सभा चुनावों के लम्बित दायित्व और आगामी लोक सभा

चुनावों पर अग्रिम व्यय, ₹17 करोड़ 40 लाख सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय और ₹15 करोड़ 23 लाख जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत जलाशय के निर्माण और मुआवज़े की अदायगी के लिए प्रावधित किए गए हैं।

4. योजना स्कीमों के अंतर्गत मुख्यतः ₹226 करोड़ HPPTCL के लिए और शिमला शहर में सरकारी भवनों/संस्थाओं की छतों पर ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु, ₹110 करोड़ 55 लाख शहरी तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने और विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं के पम्पों को बदलने इत्यादि के लिए, ₹101 करोड़ 49 लाख का भवनों तथा सड़कों के निर्माण हेतु प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ₹46 करोड़ 04 लाख कौशल विकास निगम तथा बहुतकनीकी संस्थानों हेतु मशीनरी क्रय करने, ₹33 करोड़ 66 लाख AIIMS बिलासपुर के भवन निर्माण के लिए और IGMC शिमला के चमयाणा में Phase III सुपर स्पैशलिटी ब्लॉक और मैडीकल कॉलेज, टांडा में छात्रावास के निर्माण, ₹29 करोड़ 98 लाख एशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित पर्यटन परियोजना के अंतर्गत होने वाले व्यय व जिला मण्डी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के पूर्व

व्यवहार्यता अध्ययन, ₹26 करोड़ 70 लाख जनजातीय विकास विभाग के मुख्य निर्माण कार्यों, ₹25 करोड़ 53 लाख विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों, राज्य पुस्तकालय के भवन निर्माण व केन्द्रीय विश्वविद्यालय के हरित आवरण, ₹22 करोड़ 21 लाख विकेन्द्रीकृत नियोजन व विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों, ₹17 करोड़ 59 लाख बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी के दायित्वों को पूरा करने और ₹12 करोड़ 27 लाख न्यायिक अकादमी घण्डल में निर्माण कार्यों और नए न्यायालय परिसर अंब, जिला ऊना के निर्माण इत्यादि के लिए प्रावधित किए गए हैं।

5. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। ₹91 करोड़ 94 लाख बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम, ₹84 करोड़ 13 लाख "राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि" के अंतर्गत विभिन्न राहत कार्यों हेतु, ₹50 करोड़ केन्द्रीय सड़क निधि, ₹48 करोड़ प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना, ₹39 करोड़ 60 लाख एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं व सहकारी सभाओं को ऋण, ₹39 करोड़ 17 लाख नाहन, हमीरपुर, चम्बा और नेर चौक में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, ₹30 करोड़ 78 लाख पोषण अभियान, ₹20 करोड़ 55

लाख राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ₹10 करोड़ 20 लाख सर्व शिक्षा अभियान और ₹4 करोड़ 92 लाख राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित हैं।

6. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों की रूप रेखा प्रस्तुत की है। मांगों का पूरा विवरण माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

7. इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से इन अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश करता हूँ।

**"जय हिन्द!"**

**"जय हिमाचल"**

Respected Speaker Sir,

1. With your permission, I rise to present the first and final batch of the Supplementary Demand for Grants for the year 2018-19.

2. The Supplementary Demand for Grants aggregate to ₹3142 crore 65 lakh. Out of this, ₹2021 crore 69 lakh is under Non-Plan Schemes, ₹671 crore 26 lakh under the Plan and ₹449 crore 70 lakh under the Centrally Sponsored Schemes.

3. Under the Non-Plan Expenditure, a sum of ₹1438 crore 70 lakh has been provided for repayment of Ways & Means Advance, about ₹144 crore for payment of energy charges of Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited and for payment of enhanced compensation for land acquisition, ₹98 crore 91 lakh for tariff subsidy to domestic consumers of electricity etc., ₹73 crore 97 lakh for beautification of religious places and acquisition of land for development of parking lots, ₹60 crore 96 lakh is being sought as additional Grant-in-Aid to H.R.T.C. etc., ₹31 crore 16 lakh for construction of various roads and payment of compensation in compliance of Court orders, ₹29 crore 50 lakh for social security and welfare, ₹18 crore

98 lakh for clearance of pending liabilities of previous Vidhan Sabha elections and to incur the expenditure on coming Lok Sabha Elections, ₹17 crore 40 lakh for expenditure on welfare schemes of the Government and ₹15 crore 23 lakh for construction of reservoirs under Jal Se Krishi Ko Bal Scheme and for payment of compensation.

4. Major expenditure proposed under the Plan Schemes is ₹226 crore to HPPTCL and for installation of Grid connected rooftop solar plants on Government buildings/Institutions in Shimla, ₹110 crore 55 lakh for completion of construction work of Urban and Rural Water Supply schemes and replacement of pumps of various lift irrigation schemes etc., ₹101 crore 49 lakh for construction of buildings and roads. Besides, ₹46 crore 04 lakh for Kaushal Vikas Nigam and purchase of machinery of Polytechnic Institutions, ₹33 crore 66 lakh for construction of AIIMS Bilaspur, construction of Super Specialty Block Phase III in IGMC at Chamyana and construction of hostel building at Medical College Tanda, ₹29 crore 98 lakh for Asian Development Bank funded Tourism Project and for conducting pre-feasibility study by Airport Authority of

India for construction of International Standard Airport at Mandi, ₹26 crore 70 lakh for major works of Tribal Development Department, ₹25 crore 53 lakh for construction of buildings of schools/colleges, State Library and green cover of Central University, ₹22 crore 21 lakh for major works under Decentralized Planning and Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi, ₹17 crore 59 lakh for liability of Horticulture University Nauni and ₹12 crore 27 lakh for construction work of Judicial Academy Ghandal and New Court Complex at Amb, District Una etc.

5. Under Centrally Sponsored Schemes, most of it is proposed for funding ongoing or new schemes for which money has been received during the year from the Government of India. Prominent among these are: ₹91 crore 94 lakh for Flood Management Programme, ₹84 crore 13 lakh for various relief works under "National Calamity Contingency Fund", ₹50 crore for Central Road Fund, ₹48 crore for Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna (PMGSY), ₹39 crore 60 lakh for Integrated Cooperative Development Projects and loan to Cooperative Societies, ₹39 crore 17 lakh for construction of Medical Colleges in Nahan, Hamirpur, Chamba and Ner Chowk, ₹30 crore 78

lakh for Poshan Abhiyan, ₹20 crore 55 lakh for National Livestock Mission, ₹10 crore 20 lakh for Sarv Shiksha Abhiyan and ₹4 crore 92 lakh for National Rural Drinking Water Programme.

6. Hon'ble Speaker Sir, I have given a broad outline of some of the important Supplementary Demand for Grants. Complete details are given in the document presented in this August House.

7. With these words, I request this August House to pass these Supplementary Demand for Grants.

**"Jai Hind!"**

**"Jai Himachal"**